कैबिनेट ने तीन मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की बैठक में 18,509 करोड़ रुपए (अनुमानित) लागत वाले तीन रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है।

सीसीईए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इन प्रोजेक्ट्स में कसारा दृ मनमाड (तीसरी और चौथी लाइन), दिल्ली दृ अंबाला (तीसरी और चौथी लाइन) और बल्लारी दृ होसपेटे (तीसरी और चौथी लाइन) शामिल हैं।

बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में मजबूत सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। ये मल्टी–ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार किए गए हैं।

सीसीईए ने आगे बताया कि यह तीन रेलवे प्रोजेक्ट्स दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 12 जिलों से होकर गुजरेंगे और इससे भारतीय रेलवे का नेटवर्क करीब 389 किलोमीटर बढ़ेगा।

उत्कल मेल प्रकाशनी प्रा. लि. की ओर से पीतवास मिश्र द्वारा महावीर प्रिंटर्स, सी/23/1, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, राउरकेला-769004 से मुद्रित व प्रकाशित.

प्रधान संपादक
श्रीमती रीता मिश्र

सम्पादक
डॉ. पीतवास मिश्र

संयुक्त सम्पादक
डॉ. सुशील दाहिमा

प्रबंध सम्पादक
मनस्विनी मिश्र

संपादकीय कार्यालय
सी-२३/१, इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
राउरकेला - ७६९०१२, ओड़िशा
फोन : २४०१९४९ (कार्यालय)
फैक्स : (०६६१) २४०१३३२

E-mail
utkalmailnews@gmail.com

प्रधानमंत्री राहत स्कीम: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक का मुफ्त उपचार

रायगढ़। सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री राहत स्कीम (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नगदी रहित उपचार स्कीम 2025) लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद 'गोल्डन ऑवर' में त्वरित और जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध कराकर अधिकतम जानें बचाना है। स्कीम के अंतर्गत किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटरयान के उपयोग से हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में भर्ती होने योग्य पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 4 फरवरी 2025 के तहत् किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटरयान के उपयोग के कारण होने वाली (वाहनों) सड़क दुर्घटनाओं के पीडितों के नगदी रहित उपचार के लिए प्रधानमंत्री राहत स्कीम सड़क दुर्घटना पीडितों का नगदी रहित उपचार स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत् दुर्घटना पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 07 दिनों की अवधि के लिए प्रति पीड़ित अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक उपचार पैकेज के अनुसार उपचार प्रदान करेगा।

घायल अवस्था में उपचार हेतु स्थिति समान्य होते तक 24 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। रायगढ़ में 23 निजी

अस्पताल पंजीकृत स्कीम के तहत रायगढ़ में जिन 23 अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है। इनमें जेएमजी मॉर्निंग स्टॉर हास्पिटल, ओपी जिंदल हॉस्पिटल, डॉ.आर.एल. हास्पिटल, रायगढ़ मेट्रो केयर हास्पिटल, अपेक्स सूपर स्पेशलिटी हास्पिटल, संजीवनी नर्सिंग होम, राजप्रिय हास्पिटल, सिद्धेश्वरी हास्पिटल, शिव हास्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, रायगढ़ आर्थो एवं जनरल हॉस्पिटल, पदमावती हास्पिटल, डॉ.आर.पटेल यूरोलाजी एण्ड मल्टी स्पेशलिस्ट, कान्हा हास्पिटल, श्री जनक हास्पिटल, उमा मेमोरियल सर्जिकल नर्सिंग होम, हरिकमल संजीवनी हेल्थ केयर, लोकेश हास्पिटल, अंकूल हास्पिटल, ग्लोबल हास्पिटल, गुरूदेव हास्पिटल, मॉ अम्बे नर्सिंग होम, गंगा स्मार्ट हास्पिटल एवं गंगा नर्सिंग होम शामिल है।

इस स्कीम के तहत् सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरयान दुर्घटना निधि (कोष) की स्थापना की गई है, जिससे पीडितों की उपचार की व्यवस्था की जा सके। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए निधि के दो खातों का उपयोग किया जायेगा, अर्थात (1) बीमाकृत यानों के लिए खाता (2) अबीमाकृत यान के लिए खाता। इस स्कीम के तहत दुर्घटना के बाद गोल्डन ऑवर जो कि सड़क दुर्घटना के बाद एक घंटा का समय होता है, इस महत्वपूर्ण समय में घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा या अस्पताल पहुंचाने से जान बचाने की संभावना सबसे अधिक होती है, जिसमें तुरन्त इलाज मिलने पर गंभीर क्षति को कम किया जा सकता है। इस जीवनरक्षक गोल्डन ऑवर के दौरान निःशुल्क बिना किसी भुगतान के पीड़ित को समय पर अपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराना है।.स्कीम के तहत् किसी भी सड़क पर मोटरयान (सड़क दुर्घटना) प्रयोग के कारण सड़क दुर्घटना का पीड़ित कोई भी व्यक्ति जिसे अस्पताल में भर्ती होने जितनी चोटे लगी है. स्कीम के अधीन अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक नगदी रहित उपचार पाने के लिए पात्र होगें। जिन पीड़ितों को दुर्घटना के समय से 24 घंटे के बाद पहली बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्हे इस स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा। ।

बृजमोहन अग्रवाल ने अमित शाह को पत्र लिखा, रायपुर को बाढ़ के खतरे से सुरक्षित करने की मांग रखी

रायपुर। राजधानी रायपुर में लंबे समय से चली आ रही जलभराव और शहरी बाढ़ की समस्याओं के निपटारे और बाढ़ के बढ़ते खतरे से स्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ध्220 करोड़ के व्यापक श्शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रमश (न्त. इंद थ्सववक त्पेा डंदंहमउमदज च्तवहतंउ) को सैद्धांतिक मंजूरी

देने का अनुरोध किया है। अग्रवाल ने पत्र में उल्लेख किया कि रायपुर शहर के लिए इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत ध्220 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति का प्रस्ताव छक्ड। को प्रस्तुत किया गया था। 10 नवंबर 2025 को जारी नवीन दिशानिर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किए गए, जिसे 23 जनवरी 2026 को राज्य कार्यकारी समिति से विधिवत स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। तकनीकी सलाहकार समिति (ज।ब्) द्वारा दिए गए सभी सुझावों एवं टिप्पणियों का समाधान करते हुए अनुपालन रिपोर्ट सहित संशोधित प्रस्ताव पत्र क्रमांक 504ध् पीडब्ल्यूडीध्एनएनआरध्2026 के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके बावजूद अंतिम स्वीकृति लंबित है। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि,रायपुर के तेजी से होते शहरीकरण के कारण यहाँ का ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर (निकासी व्यवस्था) पीछे छूट गया है, जिससे मानसून के दौरान गंभीर जलभराव की स्थिति बन जाती है। भाठागांव, प्रोफेसर कॉलोनी और अवंती विहार जैसे निचले इलाकों के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जहाँ भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और जनजीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है।बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि, ष्जुलाई 2025 में, रायपुर में 33 घंटों के भीतर 103 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई थी और प्रमुख चौराहे ठप हो गए थे। यह फंड शहर के स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण होगा।

MCL महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कम्पनी)

सूचना

"सामग्रीयों की खरीद कार्यो एवं सेवाओं के लिए सीआईएल एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा जारी सभी निविदाएँ कोल इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट www.coalindia.in/सम्बंधित अनुषंगी कम्पनी (एमसीएल, www.mahanadicoal.in), सीआईएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://coalindiatenders.nic.in एवं सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://eprocure.gov.in पर उपलब्ध है या इसके अतिरिक्त, जीईएम पोर्टल https://gem.gov.in के माध्यम से भी खरीद की जाती है।"

R-5286

ओड़िशा की पहली एआई शार्ट फिल्म 'निहसारता' एक नए युग की शुरूआत

भुवनेश्वर : ओडिशा की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपनी पहली AI–ड्रिवन शॉर्ट फिल्म, निहसारता की रिलीज के साथ एक माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रही है। ओली प्लस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी कल्पना के साथ मिलाकर एक यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है। युवा फिल्ममेकर शुभ्रकांत साहू ने इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट सोचा और डायरेक्ट किया। उन्होंने जोर दिया कि निहसारता सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह पता लगाने की एक एक्सपेरिमेंटल कोशिश है कि AI ओडिया सिनेमा को कैसे नया आकार दे सकता है। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी को इंसानी भावनाओं के साथ मिलाकर ऑडियंस के लिए कुछ नया पेश करता है। फिल्म को कोलेबोरेटर बिस्वजीत दाश, सौम्या बाला, मनोरंजन ओझा और लक्ष्मीनारायण से काफी सपोर्ट मिला। उनके डेडिकेशन ने विजन को हकीकत में बदलने में मदद की। साथ मिलकर, टीम ने दिखाया कि कैसे AI पारंपरिक कहानी कहने के तरीकों को कॉम्प्लिमेंट कर सकता है और नई क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज खोल सकता है। अभी ओली प्लस एंटरटेनमेंट के ल्वनज्नइम चौनल पर स्ट्रीमिंग हो रही निहसारता ने पहले ही इनोवेशन के लिए उत्सुक दर्शकों का ध्यान खींचा है। ऑडियंस इसके अलग फ्लेवर और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की तारीफ कर रही है, जो इसे ओडिशा में भविष्य के AI –पावर्ड प्रोडक्शन्स की ओर एक उम्मीद भरा कदम बनाता है। शुभ्रकांत साहू ने दर्शकों को फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित किया, और ओडिया सिनेमा में एक पायनियरिंग प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी भूमिका पर जोर दिया। उनका मानना घ्है कि निहसारता एक नए चौप्टर की शुरुआत है जहाँ टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी मिलकर कहानी कहने के तरीके को फिर से परिभाषित करती हैं। इस रिलीज के साथ, ओडिशा भारत में AI सिनेमा में सबसे आगे है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे रीजनल इंडस्ट्रीज कल्चरल पहचान से जुड़े रहते हुए इनोवेशन को अपना सकती हैं। निहसारता और भी एक्सपेरिमेंट के लिए मंच तैयार करती है जो डिजिटल युग में कहानियों को कहने के तरीके को बदल सकते हैं।